Drug Licensing Policy

2788. SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether apart from the drug pricing policy Government have since evolved a separate policy covering drug licensing aspect; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Subsequent to discussions held in both the Houses of Parliament, Government announced "Modifications in the Drug Policy, 1986" on 15.9.1994, which *inter-alia* include decisions of the Government in regard to both industrial licensing aspects as well as pricing aspects of Pharmaceutical Indusry. Copies of the document containing the Modifications are available in the Parliament Library.

भू-राजस्व वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना

2789. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक उत्तर प्रदेश के सभी भू-राजस्व वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री) (डा0 कृपासिंधु भोई) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल में गैस पीडितों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

2790. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) भोपाल में गैस पीडितों के पुनर्वास के लिए वर्तमान कार्य योजना की अवधि किस तिथि को समाप्त हो रही है;

(ख) इस कार्य योजना की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अपूर्ण रह गए निर्माण कार्यो को किस प्रकार पूर्ण किया जाएगा; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को आगामी पांच वर्षो के लिए कोई नई कार्य योजना प्रस्तुत की है; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) भोपाल गैस पीडितों के चिकित्सीय, आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 01.04.1990 से 31.03.1995 तक के पांच वर्षो की अवधि के लिए कुल 163 करोड़ रुपए की